हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

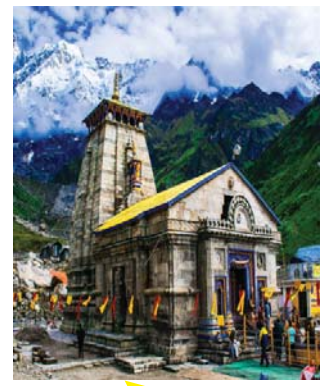

वर्ष:4 अंक:249 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, शनिवार, 13 सितंबर 2025

उत्तराखण्ड में विकास को मिली नई गति - मुख्यमंत्री ने दी 146.19 करोड़ की स्वीकृति

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विकास योजनाओं को नई ऊर्जा देते हुए 146.19 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं से शिक्षा, पेयजल, सड़क, कुम्भ मेला तैयारियों और प्रशासनिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी संजीदगी दिखा रहे है। उन्होंने जनपद नैनीताल के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर से राजकीय इंटर कॉलेज लामाचौड़ होते हुए कालाढूंगी मुख्य मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु 3.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे क्षेत्रीय जनता को सुगम यातायात सुविधा मिलेगी।

वही जनपद बागेश्वर में बोड़ी धुराफाट पम्पिंग योजना के अंतर्गत ऊर्जा कुशल सेंट्रीफ्यूगल पम्प सेटों की आपूर्ति और स्थापना सहित विभिन्न कार्यों के लिए 4.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

हरिद्वार जनपद के रोशनाबाद में अभियोजन

विभाग के जनदीय निदेशालय हेतु कार्यालय एवं सदर मालखाना निर्माण के लिए 7.07 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसमें प्रथम किस्त के रूप में 40 प्रतिशत राशि भी जारी की गई है।

आगामी कुम्भ मेला-2027 की भव्य तैयारियों के तहत लगभग 113 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये टोकन राशि निर्गत की जाएगी।

इसके साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत

उत्तराखण्ड जल संस्थान की 03 योजनाएं (लागत 9.22 करोड़)

उत्तराखण्ड पेयजल निगम की 17 योजनाएं (लागत 8.36 करोड़)

अर्थात कुल 17.58 करोड़ रुपये की 20 योजनाओं को नाबार्ड से स्वीकृति मिली है।

लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन को भी स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति योगदान का सम्मान करते हुए श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्व. श्यामदत्त तिवारी, निवासी किच्छा, उधम सिंह नगर को लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन अनुमन्य करने का अनुमोदन भी दिया है। उन्हें 14 जून 2017 से 13 अक्टूबर 2022 तक 16,000 प्रतिमाह तथा 14 अक्टूबर 2022 से 20,000 प्रतिमाह (बकाये सहित) पेंशन स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार विकास, पारदर्शिता और जनसेवा के मार्ग पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत कर खुश दिखे राज्यमंत्री सुनील सैनी

बोले- देवभूमि पर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद अमूल्य

पथ प्रवाह, संवाददाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन ने प्रदेशवासियों में नई ऊर्जा का संचार किया। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए राज्य मंत्री सुनील सैनी विशेष रूप से प्रसन्न और उत्साहित नजर आए। राज्यमंत्री सुनील सैनी ने कहा - ÷प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन उत्तराखंड के लिए अमूल्य है। आपदा की इस घड़ी में उनका संवेदनशील रुख प्रभावित परिवारों को संबल देने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में राज्य के विकास कार्य नई गति प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को नजदीक से समझा और भरोसा दिलाया कि केंद्र व राज्य सरकार पूरी शक्ति के साथ उनके साथ खड़ी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनील सैनी ने कहा कि ÷प्रधानमंत्री जी ने न केवल सहायता का आश्वासन दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी नियम में बदलाव करना पड़े तो वह भी किया जाएगा। यह उनकी संवेदनशीलता और दूरदृष्टि को दर्शाता है।

स्थानीय जनता की प्रतिक्रियाएँ

विकास नगर निवासी सुनील कुमार ने कहा - ÷प्रधानमंत्री का पीड़ितों से सीधे संवाद करना हमारे लिए बड़ी राहत है। हमें भरोसा है कि पुनर्निर्माण कार्य तेजी से होंगे। व्यापारी संघ के पदाधिकारी और भाजपा के जिला मंत्री संजीव चौधरी ने कहा - राज्यमंत्री सुनील सैनी और मुख्यमंत्री धामी जी का उत्साह देखकर हमें विश्वास है कि केंद्र-राज्य मिलकर आपदा राहत में तेजी लाएंगे।

केंद्र सरकार से आपदा राहत को मजबूती - उत्तराखंड को मिले 455.60 करोड़ रुपये

पथ प्रवाह, देहरादून

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के केंद्रीय अंश के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 455 करोड़ 60 लाख रुपये अग्रिम तौर पर जारी किए हैं। यह स्वीकृति 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि यह राशि उत्तराखंड में आपदा राहत एवं पुनर्वास कार्यों में इस्तेमाल की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संकट की घड़ी में उत्तराखंड का संबल बने हैं, जिसके लिए राज्य की जनता उनका विशेष आभार व्यक्त करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण, त्वरित राहत और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने उप राष्ट्रपति पद की शपथ ली

नयी दिल्ली। श्री चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को देश के 15 वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में श्री राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलायी।

इससे पहले श्री राधाकृष्णन के उप राष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित निर्वाचन आयोग का प्रमाण पत्र पढकर सुनाया गया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड, वेंकैया नायडू , हामिद अंसारी , लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह , केन्द्रीय मंत्री प्रकाश नड्डा , नितिन गडकरी और कई अन्य केन्द्रीय मंत्री तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद 9 सितम्बर को उप राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया था। इस चुनाव में केंद्र में सत्तारूढ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदावार रहे श्री राधाकृष्णन निर्वाचित घोषित किये गये थे। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार श्री बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के बड़े अंतर से हराया । राधाकृष्णन अब तक महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। चार मई, 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे श्री राधाकृष्णन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक हैं। उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक के रूप

में शुरु किया और अब वह देश के उप राष्ट्रपति चुने गये हैं।

श्री राधाकृष्णन ने सार्वजनिक जीवन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक के रूप में शुरु किया और सन 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने।

उन्हें 1996 में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सचिव नियुक्त किया गया। वे 1998 में कोयंबटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 1999 में वे पुनः लोकसभा के लिए चुने गए।

सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कपड़ा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) संबंधी संसदीय समिति और वित्त संबंधी परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे। वह स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जाँच करने वाली संसदीय विशेष समिति के सदस्य भी थे। राधाकृष्णन ने 2004 में, संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वह भारत से ताइवान गए पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थे। राधाकृष्णन 2004 से 2007 के बीच, तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस पद पर रहते हुए, उन्होंने 93 दिनों तक चली 19,000 किलोमीटर की %रथ यात्रा% की। यह यात्रा सभी भारतीय नदियों को जोड़ने, आतंकवाद के उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करने, अस्पृश्यता निवारण और मादक पदार्थों की समस्या से निपटने की उनकी मांगों को उजागर करने के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए दो और पदयात्राओं का भी नेतृत्व किया। राधाकृष्णन को 2016 में, कोच्चि के कॉयर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इस पद पर वह चार वर्षों तक रहे। उनके नेतृत्व में, भारत से कॉयर निर्यात 2532 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। वह 2020 से 2022 तक, भाजपा की केरल इकाई के प्रभारी रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात

पथ प्रवाह, योगेश शर्मा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से भेंट कर राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास, हवाई सम्पर्क में सुधार एवं पर्यटन को नई गति देने से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य को विमानन क्षेत्र में मिले सहयोग के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश के हवाई अड्डों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु अम्ब्रेला ब्राण्ड 'हाउस ऑफ हिमालयाज' के अंतर्गत कियोस्क स्थापित किए जाने की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे राज्य में स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य में मानसून समाप्ति के बाद चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवाओं को पुनः प्रारंभ करने की योजना से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। यह सेवाएं विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग एवं असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के मध्य इस विषय पर समन्वय जारी है। विगत 01 सितम्बर को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में हेली सेवाओं के संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करते हुए हेली सेवाओं का पुनः संचालन यात्रा को सहज बनाएगा एवं सड़क मार्गों पर दबाव कम करेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य का 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। राज्य में विशेषकर पर्वतीय जिलों में हवाई सम्पर्क न केवल आवश्यक है, बल्कि पर्यटन, नागरिक आवागमन तथा आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने गौचर (चमोली) एवं चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) हवाई पट्टियों को छोटे विमान संचालन के लिए विकसित करने एवं इन्हें दिल्ली, देहरादून तथा हिंडन से जोड़ने का अनुरोध किया। इससे चारधाम यात्रा की सुविधा बढ़ेगी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भी सुगमता रहेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर रात्रिकालीन हवाई सेवा के संचालन का भी केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को विमान सेवा का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर भी चर्चा की और बताया कि राज्य सरकार द्वारा अधिकांश आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को शीघ्र कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने केंद्रीय मंत्री से क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के तहत दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए नियमित हवाई सेवा शीघ्र प्रारम्भ करने का अनुरोध करते हुए बताया कि राज्य के पर्यटन के साथ-साथ सामरिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से भी हवाई सेवा लाभकारी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी का निरीक्षण कर हवाई सेवा का संचलान किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने का भी केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से अनुरोध किया।

एक नजर

हरिद्वार में प्रधान जी समेत 26 घरों में पकड़ी बिजली चोरी, मुकदमा दर्ज

पथ प्रवाह, हरिद्वार। विजिलेंस की टीम ने शुक्रवार को विद्युत वितरण उपखण्ड जगजीतपुर क्षेत्र के ग्राम सराय और जमालपुर में बिजली चोरी रोकने के लिए जोरदार छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान ग्राम प्रधान मनीष समेत 26 लोगों के घरों में बिजली चोरी को पकड़ा है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी जगजीतपुर रूपेश कुमार ने बताया कि विजिलेंस की टीम ने सराय और जमालपुर गांव में छापेमारी की गई। बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों में रवि पुत्र जयपाल, मनीष पुत्र जगपाल, मांगेराम पुत्र लाल सिंह, राजेश (काला) पुत्र वेदी, ज्ञान सिंह पुत्र हरिचंद, श्रवण पुत्र राज जस्सा, विजय पाल पुत्र मंगत राम, काशी राम पुत्र बुच्चा, दीप चंद पुत्र पाल्ला, काका पुत्र रामनाथ, ओमप्रकाश पुत्र खुशहाल सिंह, मोहन कुमार पुत्र राजेंद्र, सतीश पुत्र हरनंद सिंह, जगपाल सिंह पुत्र मंगत राम, जगपाल पुत्र हरनंद, आशीष दास पुत्र मधुसुधन दास, सीमा पत्नी जितेंद्र, सन्दीप कुमार पुत्र नाथी राम, रिंकु पुत्र समनाथ, अजय पुत्र धमेन्द्र पुत्र मांगे राम, अत्तर सिंह पुत्र चिमन, राजू पुत्र अत्तर सिंह, तिलक राम पुत्र मुल्लर, वेदपाल पुत्र हरिचंद और प्रवेश पुत्र जसमत शामिल हैं। कार्रवाई में सहायक अभियंता (सतर्कता) धन्नजय कुमार, रोबिन सिंह, विकास कुमार, अनिल सिंह, उपखण्ड अधिकारी जगजीतपुर रूपेश कुमार, अवर अभियंता वरुण पंवार, प्रिति जिंटा, सपना, अनिता काला, निरीक्षक मारूत शाह, सरिता शाह और उपनिरीक्षक संदीप त्यागी शामिल रहे। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पकड़े गए सभी लोगों पर नियमों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। साथ ही चेतावनी दी कि बिजली चोरी करने वालों पर आगे भी इसी तरह की सख्त छापेमारी अभियान जारी रहेंगे।

जटिल पारिवारिक विवादों में काउंसलिंग कर 5 परिवारों को टूटने से बचाया

पथ प्रवाह, हरिद्वार। रिजर्व पुलिस लाईन रोशनाबाद हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के दिशा-निर्देशन में पुलिस उच्चाधिकारीगण की देखरेख में बिखरते परिवारों को जोड़ने के लिए महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिला हेल्पलाइन हरिद्वार में प्रचलित जटिल पारिवारिक विवादों व दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर सुना गया। इस दौरान पांच परिवारों को टूटने से बचाया गया। तीन प्रकरणों में सोचने समझने के लिए अग्रिम तिथि दी गई। बैठक में नोडल अधिकारी महिला सुरक्षा/ हेल्पलाईन, सुश्री निशा यादव (सहायक पुलिस अधीक्षक), मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर अरूण कुमार, समाजशास्त्री विनोद शर्मा, अधिवक्ता रीमा साहीम, समाज सेविका रंजना शर्मा (प्रधानाचार्य), प्रभारी महिला हेल्पलाइन मायापुर उपनिरीक्षक अंशु चौधरी, कांस्टेबल पंकज रावत व महिला कांस्टेबल आंचल मनवाल द्वारा प्रतिभाग किया गया।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने यात्रियों को किया जागरूक

पथ प्रवाह हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल के दिशा-निर्देशन में, सश्पुश्अश्/नोडल अधिकारी एएचटीयू हरिद्वार के पर्यवेक्षण में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा यात्रियों को लगातार जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। जनपद हरिद्वार की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा आरपीएफ और जीआरपी के साथ संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन हरिद्वार पर बाहर से आए यात्रियों को गोष्ठी के माध्यम से जागरूक किया गया। टीम द्वारा यात्रियों को मानव तस्करी, नशाखोरी, बाल भिक्षावृत्ति एवं साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। यात्रियों को बताया गया कि यात्रा करते समय अपने सामान, बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। किसी अंजान व्यक्ति से खाने-पीने का सामान न लें तथा किसी भी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास न करें। यात्रा के दौरान यदि कोई बालक/बालिका संदिग्ध अवस्था में मिले अथवा किसी यात्री के साथ कोई घटना घटित हो जाए तो इसकी सूचना तत्काल टोल-फ्री नंबर 112 पर दें। बाहर से आए यात्रियों ने गोष्ठी में दी गई जानकारी की सराहना की। इसी क्रम में टीम द्वारा आरपीएफ हरिद्वार के साथ आपसी समन्वय गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें आपसी कार्यों की समीक्षा एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया।

लिव इन पार्टनर की हत्या कर खुद ही कोतवाली पहुंच गया हत्यारोपी

धीरज शर्मा, हरिद्वार।

हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से एक महिला की हत्या का सनसनी खेज मामला सामने आया है। हत्यारोपी महिला का मित्र ही है। आरोपी ने हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद खुद कोतवाली पहुंच कर सरेंडर किया। पुलिस भी उसकी बात सुनकर चौंक गई। पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया और मौके पर पहुंच कर शव को बरामद कर लिया। हत्यारोपी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी और इस वक्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का वाहन चालक है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया सामने आई जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम मुकेश कुमार उर्फ मुकेश पुजारी है। महिला हरिद्वार की रानीपुर कोवताली क्षेत्र में रहती थी। महिला पिंकी अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मुकेश और पिंकी से एक नौ साल की बेटी है। जबकि मुकेश की धर्मपत्नी से दो बच्चे हैं। दोनों शिवलोक कालोनी में किराये का मकान लेकर रहते थे। दोनों पिछले 11 साल से लिवइन में साथ रह रहे थे। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया सामने आया कि मुकेश को शक था कि पिंकी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर बीते गुरुवार रात को दोनों के बीच बहस हुई और मुकेश ने गुस्से में आकर लोहे की रॉड से महिला के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। जिससे महिला की मौत हो गई। आरोपी सुबह करीब पांच बजे खुद कोतवाली रानीपुर पहुंचा और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस ब्यूटी पार्लर पहुंची जहां अंदर पिंकी का खून से लथपथ शव पड़ा था। रानीपुर कोतवाल शांति कुमार ने बताया कि शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है।

आपको बताते चलें कि जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ आरवी सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि मुकेश की नियुक्ति स्थायी है और घटना की जानकारी विभाग को मिली है। वर्तमान समय में वो एसीएमओ का वाहन चालक है। रानीपुर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतका के पिता ने कोतवाली रानीपुर में आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी है।

शादी का झांसा देकर फरार हुआ 5 हजार का इनामी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले पांच हजार के इनामी को श्यामपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था।

पुलिस के मुताबिक 30 जुलाई 2025 को पीड़िता द्वारा थाना श्यामपुर पर शिकायत दर्ज करायी थी कि रितेश यादव पुत्र मुनेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम बहावपुर थाना फतेहपुर कोतवाली जिला बाराबंकी (उ0प्र0) द्वारा पीडिता से प्रेम प्रसंग कर शादी का वादा कर शारीरिक सम्बन्ध बनाए और बाद में शादी करने से इंकार कर

दिया। जिस पर पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध थाना श्यामपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सम्भावित स्थानों पर पूर्व में कई बार दबिशें डाली गई परन्तु आरोपी लगातार फरार चल रहा था तथा गिरफ्तारी से बचने के लिये लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय से गैर जमानती वारण्ट प्राप्त कर तथा आरोपी पर पांच हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था। पुलिस टीम ने इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के माध्यम से ईनामी रितेश यादव को जिला बाराबंकी (उ0प्र0) से गिरफ्तार कर लिया।

नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अभिलेखों की जांच प्रक्रिया पूर्ण, हरिद्वार जिला अध्यक्ष सुदेश आर्या के प्रयासों की सराहना

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

हरिद्वार। नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (प्रदेश स्तरीय पत्रकार संगठन) के अभिलेखों संबंधी जांच प्रक्रिया शुक्रवार को उप रजिस्ट्रार कार्यालय हरिद्वार में विधिवत पूर्ण हुई। करीब दो घंटे तक चली इस प्रक्रिया में एजेंडा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, रसीद बुक, पिछला आय-व्यय विवरण, फॉर्म जे, फॉर्म झ और सदस्यता पत्रावलियों सहित कई महत्वपूर्ण अभिलेखों का गहन परीक्षण किया गया। संगठन के व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने पर संघ निरीक्षक ने यूनियन की सराहना की, साथ ही कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए, जिन पर आगे अमल किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक त्रिलोकचंद भट्ट के नेतृत्व में हरिद्वार जिला अध्यक्ष सुदेश आर्या ने अभिलेखों के संधारण एवं जांच प्रक्रिया को पूर्ण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संरक्षक ने बताया कि वे कई सप्ताह से निरंतर इस कार्य को सम्पन्न कराने में जुटी रहीं और आज तीसरी बार श्रमायुक्त कार्यालय पहुंचीं। उनके अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप ही संगठन ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

प्रदेश अध्यक्षा दया जोशी ने भी इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन की यह उपलब्धि सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के सामूहिक सहयोग का परिणाम है। विशेष रूप से हरिद्वार जिला अध्यक्ष सुदेश आर्या का समर्पण और मेहनत अनुकरणीय है।

यह उपलब्धि संगठन को और मजबूती प्रदान करेगी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा, जिला महासचिव मुकेश कुमार सूर्या, पूर्व जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह सिद्धू सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

हरिद्वार पुलिस ने खोए हुए 11 मोबाइल किए रिकवर

पथ प्रवाह हरिद्वार। एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा ऑपरेशन रिकवरी के तहत चोरी/खोए हुये मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए गठित सीईआईआर पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 11 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किये। कोतवाली नगर हरिद्वार पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से खोए हुए 11 मोबाइल फोनो की रिकवरी की,जिनकी कीमत लगभग दो लाख अस्सी हजार रुपये है। ये मोबाइल फोन उत्तराखण्ड सहित उत्तर प्रदेश, व अन्य राज्यों से बरामद किए गए हैं। बरामद में से 04 मोबाईल स्वामी अधिक दूर होने के कारण अपना फोन लेने हरिद्वार नहीं आ पा रहे थे। पुलिस द्वारा चारों (4) मोबाईल को कोरियर सर्विस के माध्यम मोबाईल स्वामियों के पते पर भेजा। जबकि अन्य मोबाइल भौतिक रुप से उनके मालिकों के सुपुर्द किए गए। अपने खोए हुये मोबाइल फोन सही सलामत हालत में वापस मिलने पर मोबाइल स्वामियों द्वारा हरिद्वार पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया गया।

2027 कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी, मुख्य सचिव ने मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अगामी 2027 के कुंभ को दिव्य एवं भव्य ढंग से आयोजित करने के उद्देश्य और आने वाले श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्यों का मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मेला क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेला अधिकारी सोनिका, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल, उपाध्यक्ष एचआरडीए अंशुल सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने मेलाधिकारी, जिलाधिकारी एवं संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि 2027 का कुंभ दिव्य एवं भव्य ढंग से आयोजित किया जाए। इसमें जिस स्तर से जो भी स्थाई एवं अस्थाई निर्माण कार्य एवं घाटों का विस्तारीकरण आदि कार्य किए जाने है, उन कार्यों को दिसंबर 2026 तक पूर्ण कर लिए जाए तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टिगत जिन घाटों पर रेलिंग लगाई जानी है उन घाटों पर प्राथमिकता से रेलिंग का कार्य किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जो कार्य किए जाने है उन कार्य को तत्परता एवं समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिए गए।

जनपद आगमन पर मेलाधिकारी सोनिका,जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पुष्प गुच्छ भेंटकर मुख्य सचिव का स्वागत किया। मेलाधिकारी सोनिका एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मुख्य सचिव को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए उनका संबंधित अधिकारियों से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान प्रमुख अभियंता सिंचाई सुभाष चंद पांडे,मुख्य अभियंता सिंचाई चंद्र शेखर सिंह,डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध,अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती,सचिव एचआरडीए मनीष सिंह,उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार,एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा,एसपी सिटी पंकज गैरोला, सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, अधीक्षण अभियंता लोनिवि डीके सिंह,अभियंता सिंचाई ओमजी गुप्ता,अधिशासी अभियंता लोनिवि दीपक कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

इन कार्यों का मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण

मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों द्वारा नजीबाबाद हाईवे पर गौरी पार्किंग स्थल में मल्टी मॉडल हब बनाये जाने हेतु कार्य का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा चण्डी देवी मन्दिर तक रोपवे का निर्माण हेतु स्थलीय निरीक्षण, दिव्य प्रेम मिशन आश्रम के समीप नीलधारा में कल्चरल हब के निर्माण की योजना कार्य का निरीक्षण, नमामिः गंगे घाट नीलधारा में लेजर शो हेतु स्थिल निर्माण की योजना का निरीक्षण,बैरागी कैम्प क्षेत्र में विभिन्न अखाड़ों एवं धार्मिक संस्थाओं के कैम्पिंग की योजना का निरीक्षण, बैरागी कैम्प क्षेत्र, दक्षद्वीप क्षेत्र में मायापुर स्कैप चैनल के दोनो 15 और नये घाटों के निर्माण कार्य की योजना का निरीक्षण,आईरीस सेतु से श्री यंत्र मन्दिर होते हुए मातृ सदन तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण योजना का एवं उक्त मार्ग के मध्य 700 से 800 मी0 की कच्ची सड़क को पक्की सड़क बनाने जाने की योजना कार्य का निरीक्षण,नक्षत्र वाटिका के समीप कनखल ऐरिया कैनाल फ्रन्ट डेवलपमेन्ट योजना जिसके अन्तर्गत नक्षत्र वाटिका के पास पार्किंग ऐरिया, लैण्ड स्कैपिंग, पैदल स्थाई पुल चौड़ाई 7.0 मी0 (01 पुल दक्ष मन्दिर को जोडने हेतु एवं 01 पुल बैरागी क्षेत्र से सतीघाट को जोड़ने हेतु) कार्य का निरीक्षण, शमशान घाट कनखल के सामने 01 नग अतिरिक्त स्थाई सेतु के निर्माण कार्य का निरीक्षण,आनन्दमयी पुलिया से जान्ह्वी डेल होटल तक सिल्टइजैक्टर के ऊपर सड़क निर्माण की योजना कार्य का निरीक्षण,आनन्दमयी पुलिया से झंडा चौक कनखल है होते दक्ष मन्दिर मार्ग का निरीक्षण एवं झंडा चौक कनखल के चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण,भीमगोड़ा स्थित खड़खड़ी शमशान घाट को चमगाद्ध टापू से जोड़ने हेतु स्थाई सेतु निर्माण कार्य का निरीक्षण एवं हरकी पैड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया।

अपनी बदहाली पर आंसू बहाता '52 शक्तिपीठों का जननी स्थल पौराणिक सतीकुंड'

धीरज शर्मा, हरिद्वार।

दुनियाभर में मां के 52 शक्तिपीठ स्थित है। जहां पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।लेकिन इसे दुर्भाग्य ही माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन 52 शक्तिपीठों की जननी आज भी बदहाली की मार झेल रही है।हालत यह है कि बड़े-बड़े सरकारी दावों के बावजूद आज भी कनखल स्थित पौराणिक सतीकुंड अर्थात 52 शक्तिपीठों की जननी सरकारी उपेक्षा के चलते बर्बादी की कगार पर है बस चंद लोग आज भी इस सतीकुंड का अस्तित्व बचाए रखे हुए हैं।

इस सतीकुंड के जीर्णोद्धार के लिए तत्कालीन तिवारी सरकार में यहां पर कुछ जीर्णोद्धार के कार्य कराए गए। 2016 के अर्ध कुंभ में जरूर यहां पर कुछ साफ सफाई पुताई कर इतिश्री कर ली गई।2021 में मेला प्रशासन इस पौराणिक स्थान को पूरी तरह से भूल गया। बीते महाकुंभ के दौरान प्रदेश सरकार ने इस पौराणिक सती कुंड के जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी। जिसके तहत यहां पर कई महत्वपूर्ण काम होने थे। लेकिन वह धनराशि कहां गई ? इसकी कोई जानकारी नहीं है।

स्कंद पुराण में वर्णित है सती कुंड का इतिहास

स्कंद पुराण के केदारखंड में वर्णित कथा के अनुसार हरिद्वार की पौराणिक नगरी कनखल राजा दक्ष की नगरी कहलाती है। पुराणों के अनुसार राजा दक्ष ने इसी कनखल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था,

जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजकर सादर आमंत्रित किया था।लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव और सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। पिता मोह में माता सती अपने पति भगवान शिव के मना करने के बाद भी यज्ञ में पहुंचीं।मगर जब मां सती ने यज्ञ में अपने पति का आसन लगा नहीं देखा, तो इसे अपने पति का अपमान समझा और मां सती ने इससे नाराज होकर सतीकुंड में बने हवन कुंड में कूदकर जान दे दी थी।

सती के हवनकुंड में आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति कर राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। इसी स्थान पर वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर भी धड़ से अलग कर दिया था। सती के हवन कुंड में कूदने के बाद भगवान शंकर क्रोध में सती का शरीर लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जले हुए शरीर के 52 टुकड़े किए। यह 52 टुकड़े पृथ्वी पर 52 स्थानों पर गिरे कालांतर में उन्हें 52 शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है।

इसी स्थान पर राजा दक्ष ने किया था यज्ञ

सतीकुंड वही स्थान है, जहां पर राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। हरिद्वार को पंचपुरी भी कहा जाता है। हरिद्वार को पांच भागों में विभाजित किया गया है। शांतिकुंज से मायापुर तक मायापुरी, मायापुर से कनखल तक दक्षपुरी, दक्ष कनखल से जगजीतपुर तक जगजीतपुरी, मिश्रपुरी और ज्वालापुरी है। शिवपुराण के अनुसार राजा दक्ष के यज्ञ आयोजन को 12 सौ योजन में किया गया था। यहां बनाया गया हवन कुंड 12 सौ योजन तक फैला हुआ था।जिस स्थान पर आज सती कुंड मौजूद है, यह वही स्थान है, जहां पर बैठकर राजा दक्ष ने यज्ञ की आहुति दी थी, जो दक्ष मंदिर आज विद्यमान है।इसी स्थान पर आए भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ के दौरान भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच दी थी और यज्ञ तहस-नहस कर दिया था।

माता सती के शरीर के हो गए थे 52 टुकड़े

इसी स्थान पर बनाए गए हवन कुंड स्थल से भगवान शंकर क्रोधित होकर माता सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड भ्रमण करने लगे। भगवान विष्णु ने जब अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 52 टुकड़े करे, तो उसमें से एक अंग जहां माई की कोहनी गिरी हिंगला देवी शक्ति पीठ कहलाता है। यह शक्ति पीठ वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहा जाता है कि इस दौरान जहां जहां भगवान शंकर की आंख से आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 52 टुकड़े हुए। जहां-जहां यह टुकड़े गिरे वहां वहां, एक देवी और भैरव की उत्पत्ति होती गई। इस तरह देश में 52 शक्तिपीठों की उत्पत्ति कनखल के इसी सती कुंड से हुई।

राजा दक्ष ने नहीं किया था पुत्री सती को आमंत्रित

कहा जाता है कि सती के लिए एक से बढ़कर एक वर आ रहे थे। लेकिन माता सती ने भस्म धारी भोले शंकर को ही अपना पति मान लिया था।गले में नाग और शरीर पर भस्म धारण करने वाले भगवान शंकर को उनके ससुर राजा दक्ष बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यही कारण था कि अपने यहां किए गए आयोजन में उन्होंने न तो भगवान शंकर को निमंत्रण भिजवाया था और ना ही माता सती को बुलाया, सती कुंड में आयोजित यज्ञ में राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों और उनके पतियों को आमंत्रित किया था लेकिन माता सती और भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं रखा था। भगवान शंकर के मना करने के बावजूद माता सती जिद पर अड़ गई और उन्होंने भगवान शंकर को कहा कि बेटी अपने पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती है। वे भगवान शंकर की उपेक्षा कर कनखल आ गई। भगवान शंकर ने उनके साथ अपने गणों को भेजा था।

भगवान शंकर ने किया था रोकने का प्रयास

कहा जाता है भगवान शंकर की बात न सुन जब सती अपने पिता राजा दक्ष के यहां रवाना हुई तो भगवान शंकर ने उन्हें 10 दिशाओं से रोकने का प्रयास किया था, जिससे 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि जब क्रोध मं् भरकर माता सती इस दक्षपुरी के अग्नि कुंड में समाई थीं, तो वह एक माया थी। जिसका असर आज तक देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में कहीं भी माया का प्रवेश इसीलिए नहीं होता, क्योंकि यह नगरी पूरी तरह से श्रापित है।

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने पुलिस लाइन में जवानों के साथ लगायी दौड़

पथ प्रवाह हरिद्वार।

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने पुलिस लाइन में जवानों की परेड़ का निरीक्षण किया। इस दौरान परेड में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और जवान शामिल हुए। जवानों के साथ दौड़ लगाते हुए कप्तान ने फिटनेस और अनुशासन पर जोर दिया।

एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के निर्देश पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में शुक्रवार सुबह परेड के दौरान जनपद के सभी राजपत्रित पुलिस ऑफीसर्स, सभी थाना प्रभारी, यातायात पुलिस

एवं जवानों द्वारा शिरकत की गई। एसएसपी को सलामी देने के पश्चात शुरू हुई परेड में जवानों द्वारा असलाह के साथ परेड मैदान में दौड़ लगाई गई। उसके बाद ड्रिल का अभ्यास किया गया। परेड के बाद एसएसपी हरिद्वार ने अन्य अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन मैस सहित अन्य मदों का निरीक्षण करते हुए कमियां सुधारने के निर्देश दिए।

प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को विशेष तौर पर जवानों के लिए स्वादिष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्षेत्राधिकार लाइन एवं प्रसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया कि परेड में अधिक से अधिक कर्मचारी कर्मचारियों को बुलाया जाए जिससे कि सभी लोगों की नियमित फिटनेस बनी रहे। लाइन परिसर में भ्रमण के दौरान जिन स्थानों पर कमियां पाई गई मौके पर उपस्थित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के आदेश दिए गए।

पुलिस विभाग में शुक्रवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जनपद के पुलिस मुखिया द्वारा प्रातः काल पुलिस लाइन परेड मैदान में पहुंचकर सभी जवानों की शस्त्र अभ्यास/ड्रिल का निरीक्षण करते हुए जवानों के बीच उनके सुख सुविधाओं एवं अन्य समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उसका हर संभव समाधान का प्रयास किया जाता हैद्य इसके साथ ही पुलिस लाइन परिसर में अवस्थित विभिन्न शाखाओं का भौतिक निरीक्षण कर परिलक्षित हो रही कमियों का संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के जरिए समाधान कराया जाता है।

संपादकीय

नीति और नियत से नवा भारत !

भारत आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है, जहाँ आर्थिक नीतियां केवल वित्तीय संतुलन का उपकरण नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन चुकी हैं। जीएसटी परिषद का हालिया निर्णय इसका सशक्त प्रमाण है। दरों को सरल बनाकर पाँच और अठारह प्रतिशत की दो श्रेणियों में सीमित करना तथा विलासिता और नुकसानदेह वस्तुओं पर उच्चतम दर लागू करना केवल कर ढांचे की जटिलताओं को कम करने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि सरकार नागरिकों और कारोबारियों के बीच विश्वास को प्राथमिकता देती है। महामारी के समय राज्यों की आय-हानि की भरपाई हेतु उठाए गए ऋण को उपकर से सीमित अवधि में चुकता करने का संकल्प भी यही दर्शाता है कि सरकार आर्थिक अनुशासन और संघीय सहयोग दोनों पर समान रूप से केंद्रित है। लेकिन मोदी सरकार का दृष्टिकोण केवल कर सुधार तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अगली पीढ़ी के सुधारों की घोषणा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की नीतियां आज नहीं, आने वाले कल की चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखकर गढ़ी जा रही हैं। यही दूरदर्शिता राष्ट्र निर्माण की सच्ची कसौटी है। सुधारों का मकसद केवल आंकड़े सुधारना नहीं, समाज की संरचना को मजबूत करना, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुँचाना और हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। विनिवेश पर नए सिरे से दिया गया जोर इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। अब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि विनिवेश केवल राजस्व जुटाने का साधन नहीं, यह शासन व्यवस्था को अधिक चुस्त, पारदर्शी और सक्षम बनाने का साधन है। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों से सरकार की हिस्सेदारी कम होने का अर्थ है निजी क्षेत्र के लिए अवसरों का विस्तार और संसाधनों का बेहतर उपयोग। इससे न केवल दक्षता बढ़ती है, रोजगार और उद्यमिता की संभावनाएं भी मजबूत होती हैं। वहीं रणनीतिक क्षेत्रों में सरकार की उपस्थिति यह संदेश देती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे संवेदनशील विषयों पर राज्य की भूमिका अपरिहार्य है। सरकार ने वार्षिक विनिवेश लक्ष्य तय करने की परंपरा समाप्त कर दी है। यह बदलाव मामूली नहीं, बेहद गहन महत्व रखता है। पहले यह प्रक्रिया अक्सर राजकोषीय घाटे को कम करने की कवायद बन जाती थी। अब यह स्पष्ट है कि विनिवेश से जुटाई गई राशि दीर्घकालिक पूंजीगत निवेश, अवसंरचना निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। इससे न केवल विकास की गति तेज होगी बल्कि भविष्य की पीढ़ियों पर सार्वजनिक ऋण का बोझ भी कम होगा।

इतना ही नहीं इन निर्णयों के पीछे जो मूल विचार है, वह है भविष्योन्मुखी दृष्टि और सामाजिक न्याय का संतुलन। कर सुधार छोटे कारोबारियों को राहत देकर स्थानीय स्तर पर उत्पादन और रोजगार को प्रोत्साहित करेंगे। इससे आर्थिक असमानता कम होगी और समाज के कमजोर वर्गों को मजबूती मिलेगी। वहीं विनिवेश से मिलने वाले संसाधन यदि शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत जरूरतों में लगाए जाएं तो यह सीधे-सीधे ज्ञानोदय की ओर बढ़ाया गया कदम होगा। यही वह बिंदु है जहाँ अंत्योदय और ज्ञानोदय आपस में मिलते हैं। सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी से ही समाज का सामूहिक उत्थान संभव है। मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास की एक स्पष्ट धारा दिखाई देती है। महामारी के कठिन दौर में राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र ने ऋण लेकर सहयोग दिया। अब उसी ऋण को समयबद्ध तरीके से चुकाने का निर्णय यह दर्शाता है कि भारत केवल आर्थिक प्रबंधन ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार शासन की मिसाल भी प्रस्तुत कर रहा है। यह विश्वास का ताना-बाना ही है जो संघीय ढांचे को मजबूत करता है और भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र को एकजुट रखता है। विकास तभी स्थायी होता है जब वह समावेशी हो। मोदी सरकार बार-बार यह संदेश देती रही है कि विकास की धारा केवल महानगरों तक सीमित न होकर गांव, किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों तक पहुँचे। कर ढांचे की सरलता, विनिवेश की पारदर्शिता और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से यही सुनिश्चित किया जा रहा है। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक महाशक्ति बनना नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाना है। विश्वास और पारदर्शिता का यह संगम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को मजबूत करता है। विदेशी निवेशक तभी किसी अर्थव्यवस्था में भरोसा करते हैं जब उन्हें नीति-निर्माण में स्पष्टता और दीर्घकालिक स्थिरता नजर आती है। हालिया निर्णय यही संदेश देते हैं कि भारत अपनी आर्थिक यात्रा में केवल अल्पकालिक राजस्व की चिंता नहीं करता, पीढ़ियों के भविष्य की चिंता करता है। कुल मिलाकर, मोदी सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियां यह प्रमाणित करती हैं कि उसका सरोकार सत्ता संचालन तक सीमित नहीं है। उसका लक्ष्य है एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण, जहाँ हर नागरिक के जीवन में विकास का प्रकाश पहुँचे, जहाँ संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण हो और जहाँ आने वाली पीढ़ियाँ एक सक्षम, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की विरासत पाएँ। यही वह यात्रा है जो अंत्योदय से ज्ञानोदय तक जाती है और जब यह यात्रा पूरी होगी, तब भारत केवल आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि विश्व को यह संदेश देने वाले राष्ट्र के रूप में उभरेगा कि विकास का वास्तविक अर्थ है विश्वास, न्याय और दूरदर्शिता का संगम। यही सच्चा राष्ट्र निर्माण है और यही मोदी सरकार की नीति और नियत का सार है।

दुनिया के देशों में कमजोर हो रहा है लोकतंत्र, न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता में सबसे बड़ी गिरावट

सनत जैन

पिछले 50 वर्षों में लोकतांत्रिक मूल्यों में सबसे बड़ी गिरावट 2019 से 2024 के बीच में देखने को मिली है। लोकतांत्रिक देश जो पहले दुनिया में मीडिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जाने जाते थे पिछले 5 वर्षों में उनके ऊपर भी बड़ा शिकंजा कसा गया है। 2024 में 173 देश के लोकतांत्रिक प्रदर्शन का आकलन द ग्लोबल स्टेट ऑफ़ डेमोक्रेसी-2025 की रिपोर्ट में हुआ है, जिसने दुनिया के 173 देश में लोकतांत्रिक मूल्यों में लगातार हो रही गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। प्रकाशित रिपोर्ट में संसदीय कार्यों में गिरावट देखने को मिल रही है। मीडिया को निष्पक्षता से काम नहीं करने दिया जा रहा है। न्यायपालिका में भी सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोगों का मीडिया और न्यायपालिका के प्रति विश्वास कम हुआ है। राजनीतिक नेतृत्व को लेकर भी आम लोगों का विश्वास घटा है, जिसके कारण लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कमजोर होती चली जा रही हैं। पिछले 5 वर्षों में 43 देशों में लोकतंत्र के इंडेक्स में भारी कमी देखी गई है। इसमें अफ्रीका के साथ-साथ यूरोप के देश शामिल हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के भी हालत तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं। यहां मीडिया के पर कतरने के लिए पत्रकारों के खिलाफ मानहानि के मामले और आपराधिक मामलों की जैसे बाढ़ आ गई है। अमेरिका जैसे देश भी इससे अछूते नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से नियमों और संस्थाओं की परंपराओं को काफी हानि पहुंची है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में भी ट्रंप प्रशासन की दखलंदाजी बढी है। भारत जो चुनाव की निष्पक्षता को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता था यहां पर भी पिछले 10 वर्षों से चुनाव की निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत के मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाने लगा है। भारत का नेशनल मीडिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों ही शामिल हैं, यह सरकार के दबाव में ही काम कर रहे हैं, जिसके कारण जनता का उनके प्रति कोई विश्वास नहीं रहा। हाल ही के वर्षों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर लोगों में अविश्वास बढ़ता जा रहा है। हाल ही में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भारत में जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं उसने सारी दुनिया के देशों को चिंता में डाल दिया है। यूरोप के देशों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जिसके कारण अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत जैसे देशों में जन समुदाय सड़कों पर आकर हिंसक प्रदर्शन करने लगा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बार-बार बल प्रयोग करना पड़ रहा है। उसके बाद भी जिस तरह बांग्लादेश और नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, नेताओं पर हमले किए गए, न्यायपालिका पर हमले किए गए, चुनाव आयोग के प्रति लोगों को विश्वास नहीं रहा। सारी दुनिया के देश अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को लेकर उनका अनुसरण करते थे। वहीं अमेरिका अब सूची में 35 वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। नागरिक अधिकारों के बारे में भी 32 वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव के माध्यम से अपने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। जिन देशों में पहले लोकतंत्र बहुत अच्छा था उनकी हालत निरंतर गिरती जा रही है। इसको लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। जर्मनी स्विट्जरलैंड नॉर्वे और लक्जमवर्ग और यूरोप के कुछ देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कोस्टा रिका चिल्ली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश लोकतांत्रिक देश के हर मायने पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश हैं। दुनिया के वह लोकतांत्रिक देश जहां पहले मानव अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सबसे बेहतर थीं वहां धार्मिक कट्टरता के माध्यम से सत्ता की सीढ़ी बनाकर सत्ता में पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके कारण धार्मिक आधार पर सत्ता पर पहुंचने के लिए जिस तरह से कट्टरता बढ़ रही है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप कर शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोग अपनी सत्ता को स्थाई सत्ता में बदलने के लिए जिस तरह के उपाय कर रहे हैं, उससे दुनिया के देशों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत तेजी के साथ कमजोर की जा रही हैं। आर्थिक असमानता लगातार गरीब, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के बीच बढ़ती चली जा रही है। दुनिया के अधिकांश देशों में इन दिनों महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी जैसे संकट देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण अब जनविद्रोह सड़कों पर देखने को मिल रहा है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की घटनाओं ने सारी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। जिस तरह से राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिका, चुनाव की निष्पक्षता, मीडिया की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं उससे अब जनक्रांति के रूप में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं उससे स्पष्ट है, कि जब लोग हर तरह से हताश हो जाते हैं, जब उनकी समस्याओं और कठिनाइयों पर कोई सुनवाई नहीं होती है, ऐसी स्थिति में आम जनता सड़कों पर आकर मुख्य पद पर बैठे हुए लोगों के साथ हिंसक व्यवहार करने लग जाती है। संसद और न्यायपालिका जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जैसे संस्थानो के भवनों को जलाया जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। रूस और यूक्रेन में वर्षों से युद्ध चल रहा है यही स्थिति इजराइल और गाजा के बीच बनी हुई है। लाखों लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। रेडक्रॉस जैसी संस्थाएं अपना वजूद खो चुकी हैं। सुरक्षा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान शांति बहाल करने की दिशा में ठोस प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनती हुई दिखने लगी है। हाल ही में इजरायल ने 6 इस्लामिक देशों में एक साथ हमला करके धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है। थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टरल असिस्टेंस की डी ग्लोबल स्टेट ऑफ़ डेमोक्रेसी 2025 की जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसने सभी को गंभीर चिंता में डाल दिया है। वर्तमान स्थिति में यदि गंभीरता के साथ बदलाव नहीं किया गया तो यह कहने में कोई कोताही नहीं है जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। यह विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की तुलना में ज्यादा खतरनाक होगा। इस समय दुनिया विकास के सर्वोच्च स्तर पर खड़ी हुई है। मशीनीकरण और घातक हथियारों का बड़ा जखीरा दुनिया के सभी देशों के पास है। इसको देखते हुए विध्वंस की केवल कल्पना ही की जा सकती है।

ये जेन जी - जेन जी क्या है..ये जेन जी?

संजीव शर्मा

जब से नेपाल में आंदोलन और सत्ता में बदलाव की खबरें मीडिया में दौड़ रही हैं तब से 'जेन जी' और 'नेपो किड्स' जैसे शब्द घर-घर में सुनाई देने लगे हैं। हालांकि नेपो किड्स हमारे देश में नया शब्द नहीं है क्योंकि मनोरंजन जगत और खासतौर पर बॉलीवुड, खेल, व्यवसाय एवं राजनीति जैसे तमाम क्षेत्रों में इसका भरपूर इस्तेमाल होता आ रहा है।

सामान्य रूप से समझे तो नेपो किड्स शब्द नेपोटिज्म से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ है भाई-भतीजावाद। यह तमगा उन युवाओं के लिए इस्तेमाल होता है जो अपने परिवार के प्रभाव के कारण राजनीति,मनोरंजन, फिल्म, खेल, व्यवसाय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से अवसर प्राप्त कर लेते हैं। इन पर यह आरोप लगता है कि वे प्रतिभा या मेहनत के बजाय अपने परिवार के नाम पर सफलता हासिल कर रहे हैं। हालांकि कई मामलों में यह बात सही नहीं है क्योंकि नेपो किड्स में कई युवा वाकई प्रतिभाशाली होते हैं और वे अपनी लगन, मेहनत और कौशल से लंबी रेस का घोड़ा साबित होते हैं।

जहां तक मौजूदा वक्त के सबसे चर्चित शब्द 'जेन जी ' या जेनरेशन जेड की बात है तो यह शब्द आमतौर पर उन युवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। जैसे भारतीय संदर्भ में परदादा, दादा, पिता और बेटे के जरिए पीढ़ियों को समझा जाता है उसी तरह पश्चिमी संदर्भ में पीढ़ियों को अलग अलग नाम से वर्गीकृत किया गया है। फिलहाल जेन जी सबसे युवा पीढ़ी है जो डिजिटल युग में पग कर एवं रच बसकर तैयार हुई है । यह पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है इसलिए कुछ लोग इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहते हैं। जेन जी को तकनीकी दक्षता, सामाजिक जागरूकता और वैश्विक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता के लिए भी जाना जाता है।

ऐसा भी नहीं है कि पीढ़ियों का नामकरण कोई पहली बार हो रहा है। दशकों से पश्चिमी समाज में बदलती पीढ़ियों को उनके दौर और तात्कालिक घटनाओं के मुताबिक अलग अलग दिलचस्प नामों से संबोधित किया जाता रहा है।

मसलन नामकरण की इस श्रृंखला की सबसे पहली एवं 1883-1900 के बीच जन्मी पीढ़ी को 'लॉस्ट जेनरेशन' कहा जाता है । यह पीढ़ी प्रथम विश्व युद्ध के समय की थी। इस समूह ने युद्ध और सामाजिक उथल-पुथल का सामना किया। इसके बाद की पीढ़ी को नाम मिला 'ग्रेटेस्ट जेनरेशन' । इसमें 1901-1927 के बीच जन्में लोगों को शामिल किया गया । देशभक्ति, कठिन परिश्रम और सामूहिक बलिदान से अपनी पहचान बनाने वाली इस पीढ़ी ने प्रथम विश्व युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव किया था।

इसके बाद नंबर आता है 'साइलेंट जेनरेशन' का । हालांकि इस नाम का इनके चुप/मौन रहने से कोई मतलब नहीं है बल्कि मौन रहकर परिश्रम करने से है। इस पीढ़ी में 1928-1945 के बीच जन्में लोग शामिल किए गए । इस पीढ़ी ने युद्ध के बाद पुनर्निर्माण का दौर देखा है और अपनी मेहनत से अपना संसार रचा था । साइलेंट जनरेशन के बाद आई पीढ़ी के नामकरण की वजह भी बहुत ही दिलचस्प है। इन्हे 'बेबी बूमर्स' कहा जाता है और इसमें 1946-1964 के बीच जन्में लोग शामिल हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्म दर में एकाएक हुई वृद्धि के कारण इस पीढ़ी को यह नाम मिला। यह पीढ़ी आर्थिक समृद्धि, सामाजिक परिवर्तन और उपभोक्तावाद के लिए भी जानी जाती है। मौजूदा वक्त में अपनी कलम, लेखन, परिश्रम, विचारों और आविष्कारों से दुनिया को समृद्ध करने वाली और अब अधेड़ हो चली पीढ़ी को 'जेनरेशन ङ्ग' कहा जाता है। इसमें 1965-1980 के बीच जन्में हम जैसे तमाम लोग शामिल हैं। हमारी यह पीढ़ी इस मामले में सबसे खास है कि इसने परंपराओं और तकनीकी बदलावों को साथ-साथ जिया है। जेन एक्स ने लैंडलाइन फोन से लेकर पेजर एवं मोबाइल फोन के विकास तक और कैसेट से फ्लॉपी,सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और अब क्लाउड स्टोरेज तक का लंबा परन्तु तेजी से बदलता सफर तय किया है।

इसके बाद आती है 'जेनरेशन वाय' अर्थात् वो लोग जिन्होंने 1981-1996 के बीच जन्म लिया है। हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे परिवार के बड़े बच्चे शामिल हैं। यह पीढ़ी डिजिटल क्रांति के शुरुआती दौर में जवान हुई है और तकनीक समझ के साथ इसके अनुभवों से भी सराबोर है।

अब आती है बारी बहुचर्चित 'जेनरेशन जेड' या जेन जी की। यह हमारी युवा पीढ़ी है क्योंकि इन्होंने 1997-2012 के बीच जन्म लिया है। मोबाइल, गेमिंग, सोशल मीडिया में डूबती उतराती इस पीढ़ी के सदस्य अधिकतम 25 से 28 साल के युवा हैं और इन्हें पढ़ाई, नौकरी, बढ़िया लाइफ और व्यक्तिगत हितों की सबसे ज्यादा फिक्र है। इसलिए यह पीढ़ी दुनिया भर में धमा चौकड़ी मचाए हुए है। ऐसा नहीं है कि पीढ़ियों का यह वर्गीकरण जेन जी पर आकर रुक गया है बल्कि इनके पीछे पीछे एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है जिसे 'जेनरेशन अल्फा' नाम मिला है। इसमें 2013 से लेकर मौजूदा साल यानि 2025 तक पैदा हुए बच्चे शामिल हैं। यह मानव सभ्यता की सबसे नवीनतम पीढ़ी है, जो पूरी तरह से 21वीं सदी में जन्मी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जनता की सेहत को लेकर संजीदा, पैकिंग में मिलेगा कुटटु का आटा

योगेश शर्मा, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के स्वास्थ्य को लेकर बेहद संजीदा दिखलाई पड़ रहे है। इसी के चलते उन्होंने नवरात्र और त्योहारी सीजन में मिलावटी कुटटु व आटा बेचने वालों पर शिंकजा कसने के निर्देश जारी किए है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफ़डीए) को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।

एफ़डीए आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि नवरात्र के दौरान उपवास में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाले कुट्टू के आटे को अब बिना लाइसेंस और पंजीकरण के नहीं बेचा जा सकेगा। कुट्टू का आटा केवल पैकिंग में ही बेचा जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित व मानक के अनुरूप उत्पाद मिल सके। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।

मानकों का पालन अनिवार्य

आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने एफ़डीए के सभी प्रभारियों, सहायक आयुक्त और अभिहित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नवरात्र अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोजित खाद्य सामग्री - विशेषकर कुट्टू का आटा निर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण और विक्रय के दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011 और संबंधित विनियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।

विभाग चरणबद्ध तरीके से चलायेगा अभियान

अभियान के पहले चरण में कुट्टू के आटे के भंडारण, संग्रहण, वितरण और विक्रय करने वाले थोक विक्रेता, डिपार्टमेंटल स्टोर और फुटकर विक्रेताओं को चिन्हित किया जाएगा। उनके यहाँ उत्पाद की जांच के साथ-साथ रखरखाव, भंडारण व लेबलिंग की शर्तों पर बैठकें आयोजित होंगी। ये बैठकें नवरात्र से पहले ही संपन्न कर ली जाएंगी।

दूसरे चरण में नवरात्र के प्रारंभ होने से पूर्व और नवरात्र अवधि के दौरान चिन्हित प्रतिष्ठानों का आकस्मिक व सामान्य निरीक्षण किया जाएगा। बिना वैध खाद्य लाइसेंस-पंजीकरण के कुट्टू के आटे का निर्माण, पैकिंग, संग्रह व विक्रय प्रतिबंधित होगा। खुले में बेचे जा रहे कुट्टू के आटे पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और खुले विक्रय को जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत हतोत्साहित किया जाएगा। कुट्टू का आटा केवल सीलबंद पैकेट में ही बेचा जाएगा। सीलबंद पैकेट पर पैकिंग तिथि, अवसान तिथि, निर्माता/रिपैकर का पूरा पता, प्रतिष्ठान का नाम और लाइसेंस नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रिकॉर्ड की निगरानी

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा खाद्य कारोबारी और उपभोक्ताओं को आपूर्ति व विक्रय पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता को कुट्टू के बीज अथवा आटे के क्रय व विक्रय का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होगा। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

क्विक रिस्पॉन्स टीम और त्वरित कार्रवाई

आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के आईडीएसपी सेल से समन्वय करते हुए कुट्टू के आटे के सेवन से बीमार होने संबंधी सूचनाओं पर क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित की जाए। यह टीम ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करेगी। नवरात्र अवधि में जनपदों से प्राप्त खाद्य नमूनों की जांच खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला स्तर पर प्राथमिकता से की जाएगी और जांच रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

उपभोक्ताओं की सेहत सर्वोपरि

अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य सरकार त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित व शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आयुक्त (एफ़डीए) डॉ. आर. राजेश कुमार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभाग ने स्पष्ट रूप से यह संकल्प लिया है कि नवरात्र जैसे पर्वों के दौरान मिलावटी, घटिया या असुरक्षित खाद्य सामग्री की बिक्री को हर हाल में रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक समन्वित, चरणबद्ध व सख्त कार्रवाई है, जिसमें निर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण से लेकर फुटकर विक्रय और ऑनलाइन आपूर्ति तक हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। विभागीय टीमें मिलावटी उत्पादों की पहचान, नमूना परीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए 24म7 अलर्ट मोड में रहेंगी। जग्गी ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन करने वाले बड़े या छोटे किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की कि यदि उन्हें कहीं मिलावटी या संदिग्ध खाद्य सामग्री की बिक्री का संदेह हो तो तत्काल विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

जिलाधिकारी करेंगे स्वास्थ्य शिविरों की मॉनिटरिंग: डॉ. धन सिंह रावत

पथ प्रवाह, देहरादून। 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' के तहत प्रदेशभर में लगभग 4114 स्वास्थ्य शिविर लगायें जायेंगे, जिनकी मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर जिलाधिकारी करेंगे, जबकि मुख्य चिकित्साधिकारी उनका सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 13 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इन स्वास्थ्य शिविरों में प्रमुख रूप से महिला स्वास्थ्य, निःक्षय मित्र एवं रक्तदान शिविरों पर विशेष फोकस रहेगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिये विभागीय अधिकारियों को रेखीय विभाग एवं स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दे दिये गये हैं ताकि आम लोगों का अधिक से अधिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित एनएचएम सभागार में 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' के अंतर्गत प्रदेशभर के जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लगभग 4114 विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाये जायेंगे। इन शिविरों का फोकस खासकर महिलाओं और बच्चों की सेहत पर होगा, जहां उन्हें जांच, उपचार और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी सेवाएं निःशुल्क मुहैया कराई जायेगी। इसके अलावा आम लोगों का भी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। इसके अलावा शिविर में स्वैच्छिक रक्तदान, टी.बी. रोगियों की स्क्रीनिंग के साथ ही निःक्षय मित्रों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। बैठक में विभागीय मंत्री ने सभी जनपदों के जिलाधिकारी को अपने-अपने जनपदों में प्रत्येक दिन स्वास्थ्य शिविरों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये, जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी उनका सहयोग करेंगे। डॉ. रावत ने कहा कि इन स्वास्थ्य शिविरों में जनपदों के प्रभारी मंत्री, स्थानीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, नगर निगमों के मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निकायों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी। इसके अलावा बैठक में महाभियान के माइक्रोप्लान, कैलेंडर, जनपद व ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता आदि बिन्दुओं पर भी विभागीय अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के साथ चर्चा की और सभी तैयारियां पुख्ता रखने के निर्देश दिये। बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, मिशन निदेशक एनएचएम मनुज गोयल, अपर सचिव स्वास्थ्य रीना जोशी, अनुराधा पाल, सलाहकार एनएचएम डॉ. तृप्ति बहुगुणा, अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर. एस. बिष्ट, डॉ. कुलदीप मर्तोलिया, डॉ. अजय नागरकर, डॉ. तुहिन कुमार, सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों ने वुर्चअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।

प्रदेशभर में लगेंगे 4114 स्वास्थ्य शिविर

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेशभर में 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' के तहत 4114 स्वास्थ्य शिविर लगाये जायेंगे। जिनमें रूद्रप्रयाग में 271, बगेश्वर 110, टिहरी 528, पिथौरागढ़ 579, चम्पावत 121, नैनीताल 368, अल्मोड़ा 519, चमोली 295, उत्तरकाशी 209, पौड़ी 324, ऊधमसिंह नगर 18, हरिद्वार 367 तथा देहरादून में 405 हेल्थ कैम्प लगाये जायेंगे।

हेल्थ कैम्प में चिकित्सक करेंगे निःशुल्क जांच

प्रदेशभर में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में विशेषकर गैर संचारी रोगों की जांच की जायेगी। जिसमें बल्ड प्रेशर, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया, सिकल सेल की जांच की जायेगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य परामर्श के साथ ही बच्चों के लिये टीकाकरण की सुविधाएं भी शिविर में उपलब्ध रहेगी।

स्वैच्छिक रक्तदान को लेगेंगे शिविर

प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में ब्लड डोनेशन कैम्प भी लगाये जायेंगे। जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में एनएसएस, स्काउट्स-गाइड्स, रोवर्स-रेंजर्स, रेडक्रॉस व रेखीय विभागों के सहयोग से रक्तदान हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा और अधिक से अधिक लोगों का स्वैच्छिक रक्तदान के लिये पंजीकरण काया जायेगा।

10 हजार निःक्षय मित्र बनाने का लक्ष्य

स्वास्थ्य शिविरों में टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जायेगी, साथ ही आम जनमानस को टीबी के प्रति भी जागरूक किया जायेगा। इसके अलावा सामुदायिक सहभागिता के तहत टीबी मरीजों के उपचार में सहयोग लिये 10 हजार निःक्षय मित्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विभागीय मंत्री ने कहा कि सामुहिक प्रयासों से ही टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य की प्राप्ति संभव है, इसके लिये विभागीय अधिकारी एवं रेखीय विभागों के अधिकारी भी स्वैच्छिक रूप से निःक्षय मित्र बनकर एक-एक टीबी मरीज को गोद लेना चाहिये। डॉ. रावत ने कहा कि 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' में निजी मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा।

ग्रामीण विकास को लेकर योजनाओं की समीक्षा करते ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी

पथ प्रवाह, देहरादून। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उत्तराखण्ड के मिलेट्स (श्रीअन्न) की देशभर में बढ़ती डिमांड को देखते हुए राज्य में इनके उत्पादों को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटक स्थलों एवं चारधाम यात्रा मार्ग जैसे प्रमुख स्थानों पर मिलेट्स आधारित बेकरी स्थापित की जाए, ताकि यहां आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक स्थानीय उत्पादों से सीधे जुड़ सकें। मंत्री जोशी ने कहा कि मिलेट्स से रस, केक जैसे इनोवेटिव बेकरी उत्पाद तैयार कर बाजार में उतारे जाएं। इससे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के संबंध में भी चर्चा की गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि कृषि विभाग के साथ शीघ्र ही संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में बीएमएम (ब्लॉक मिशन मैनेजर) के मानदेय बढ़ोतरी के विषय पर भी चर्चा हुई।

मंत्री ने अधिकारियों को हाऊस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में वे साइट एमिनिटी सेंटर स्थापित किए जाएं, जहां स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों की बिक्री हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और मिलेट्स जैसे पौष्टिक अनाज का उपयोग तेजी से बढ़ेगा।।

बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रदेश में अब तक 1.65 लाख से अधिक महिलाएं ÷लखपति दीदी÷ बन चुकी हैं, जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विकासनगर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मंडवे और झंगोरे के बिस्कुट तथा हरिद्वार जिले में सिंघाड़ा बिस्कुट तैयार करने जैसे अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान बैठक में आगामी सरस मेलों के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को इस बार के चयनित जनपद उधमसिंह नगर तथा टिहरी में आयोजित वाले सरस मेलों की सभी तैयारियां समय पर सुव्यस्थित ढंग से की जाए। बैठक में ग्राम्य विकास की अपर सचिव झरना कमठान सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

गोसेवा की सुरक्षा में जुटा हरिद्वार नगर निगम, गोवंश को पहनाई रिफ्लेक्टिव रेडियम बेल्ट

पथ प्रवाह, हरिद्वार। नगर निगम हरिद्वार ने एक अभिनव पहल के तहत गोवंश की सुरक्षा और जनसामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गोवंश को रात्रि काल में रिफ्लेक्टिव रेडियम बेल्ट पहनाने की कार्यवाही आरंभ की है। इस कदम का प्रमुख उद्देश्य रात के समय सड़कों पर घूमते गोवंश को आसानी से पहचाना जा सके और सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को न्यूनतम किया जा सके। उत्तराखंड गोसेवा आयोग के माध्यम से दिए गए निर्देशों के क्रम य?ह अभियान चलाया जा रहा है। पहले चरण में आगामी 15 दिनों के भीतर नगर क्षेत्र के 250 गोवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाने का लक्ष्य रखा गया है। नगर आयुक्त, आईएएस नंदन कुमार ने बताया कि नगर निगम द्वारा सराय क्षेत्र में 300 गोवंश क्षमता वाला गोसदन निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। शासन की व्यवस्था के अंतर्गत गोसदन के संचालन हेतु एजेंसी चयन की प्रक्रिया पशुपालन विभाग के स्तर से जारी है। रेडियम बेल्ट पहनाने की इस मुहिम की शुरुआत वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में की गई है।

गंगा की अविरलता और निर्मलता पर जिलाधिकारी सख्त, 20 से 30 सितम्बर तक होटल-व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर चलेगा विशेष अभियान

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। गंगा की स्वच्छता को लेकर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शुक्रवार को जिला गंगा समिति (नमामि गंगे) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग को आदेशित किया कि 20 से 30 सितम्बर तक विशेष अभियान चलाया जाए। इसके तहत ऐसे होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो अभी तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से नहीं जुड़े हैं, उनका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर जोड़ा जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने गंगोत्री धाम क्षेत्र में शेष बचे घरों को शीघ्र सीवर सुविधा से जोड़ने के निर्देश दिए और निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई को तत्काल डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि गंगा स्वच्छता मिशन को गति देने के लिए समयबद्ध और परिणाम आधारित कार्रवाई जरूरी है।

गौरतलब है कि उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 20 कमरों से अधिक क्षमता वाले 123 होटल पंजीकृत हैं। इनमें से 104 होटल पहले ही एसटीपी से जुड़ चुके हैं, जबकि शेष प्रतिष्ठानों को जोड़ने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। जिलाधिकारी ने साफ किया कि होटल और गेस्टहाउस से निकलने वाला गंदा पानी और अपशिष्ट सीधे गंगा या उसकी सहायक धाराओं में जाने नहीं दिया जाएगा।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिए कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाए और कचरे को गीला एवं सूखा अलग-अलग कर निस्तारित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का वैज्ञानिक निस्तारण करने और आम जनता को कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि गंगा की निर्मलता तभी संभव है जब उसकी सहायक नदियों और उनमें गिरने वाले नालों को भी प्रदूषण मुक्त रखा जाए। इसके लिए वृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि गंगा संरक्षण से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों और संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई होगी।

इस अवसर पर डीएफओ डीपी बलूनी, जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार, पर्यावरण विशेषज्ञ स्वजल प्रताप मटूड़ा, गंगा विचार मंच के प्रदेश संयोजक लोकेंद्र बिष्ट, जयप्रकाश भट्ट सहित समिति के अन्य पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यह भी तय किया गया कि गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए हर नागरिक, हर संस्था और हर विभाग को सामूहिक जिम्मेदारी के साथ आगे आना होगा।

एक नजर

चिकित्सकों की सूझबूझ से बची मरीज की जान, उपजिला चिकित्सालय पुरोला में जोखिमपूर्ण शल्यक्रिया सफल

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंहध्उत्तरकाशी। उपजिला चिकित्सालय पुरोला में गुरुवार को चिकित्सकों की सूझबूझ और कुशलता से एक गंभीर हादसे में घायल मरीज का जीवन सुरक्षित कर लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एस. रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम देवजानी निवासी मनवीर सिंह की छाती में लकड़ी का टुकड़ा फँस गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों की टीम ने तत्परता और टीमवर्क का परिचय देते हुए मरीज का सफल ऑपरेशन किया। सीएमओ ने बताया कि इस जटिल शल्यक्रिया में फिजिशियन डॉ. मनोज असवाल, सर्जन डॉ. अर्पित राय, डॉ. माही, नर्सिंग ऑफिसर हर्षमणी नौडियाल और रेडियोग्राफर अनूप नौडियाल शामिल रहे। चिकित्सकों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लकड़ी का टुकड़ा सफलतापूर्वक बाहर निकाला। यह प्रक्रिया अत्यंत जोखिमपूर्ण थी, लेकिन विशेषज्ञता और सामूहिक प्रयास से मरीज की जान बचा ली गई। फिलहाल मरीज की स्थिति सामान्य बताई गई है और वह चिकित्सकीय निगरानी में है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रावत ने पूरी चिकित्सा टीम को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सतर्कता और कौशल के कारण एक बहुमूल्य जीवन सुरक्षित हो सका।

दिल्ली हाईकोर्ट में बम की धमकी अफवाह साबित हुयी

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार सुबह बम रखे होने की धमकी मिलने के बाद पूरे परिसर की गहन जांच करायी गयी जिसमें यह धमकी अफवाह साबित हुयी। दिल्ली उच्च न्यायालय को ईमेल के जरिये धमकी मिली थी कि परिसर में तीन बम रखे गये है और इनमें अपराह्न दो बजे तक विस्फोट हो सकता है। पुलिस ने यह सूचना मिलने पर तुरंत अदालत को खाली कराया और पूरे परिसर की जांच की गयी। जांच में कहीं भी विस्फोटक या बम नहीं पाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह मेल आज पूर्वाह्न आठ बजकर 38 मिनट पर कनिमोझी थेविद्या नाम से दिल्ली हाईकोर्ट के आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजा गया था। मेल में पाकिस्तान और तमिलनाडु के आतंकी लिंक की बात कही गयी थी और कहा गया था कि न्यायालय में न्यायाधीशों के कमरों में और परिसर में बम रखे गये हैं। ईमेल मिलते ही तुरंत उच्च न्यायालय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और दिल्ली पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बम निरोधक दस्ते, स्पेशल सेल और साइबर सेल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच की । न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और न्यायालय में उपस्थित अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और पूरे परिसर को खाली कराया गया। इस दौरान न्यायालय के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गयी थी।

जिलाधिकारी ने सुनी जनता की फरियादें, विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह में निस्तारण के निर्देश

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। जनसामान्य की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने शुक्रवार को अपने कक्ष में फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं फरियादी उपस्थित हुए और उन्होंने सड़कों, पैदल मार्गों, प्रतिकर मामलों तथा राजस्व दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। जिलाधिकारी ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सभी मामलों का एक सप्ताह के भीतर निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए।

बैठक में सबसे पहले प्रवीना चौहान निवासी सौड़ ने रोजगार उपलब्ध कराने की मांग उठाई। वहीं, भटवाड़ी टैक्सी स्टैंड से जुड़े टैक्सी-मैक्सी पदाधिकारियों ने गंगोत्री तक टेम्पो ट्रैवल चलाने की अनुमति मांगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन मांगों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इसी क्रम में सुनील पंवार निवासी सौंदी गांव ने दिखोली बैंड से चोंडियाट गांव तक अवरुद्ध सड़क मार्ग को दुरुस्त कराने की मांग रखी। उन्होंने यह भी बताया कि परिसीमन के उपरांत सौंदी गांव अब उत्तरकाशी जनपद में शामिल हो चुका है, लेकिन अभी तक गांव के राजस्व अभिलेख जनपद टिहरी में ही हैं। उन्होंने इन अभिलेखों को उत्तरकाशी में स्थानांतरित किए जाने की मांग जिलाधिकारी के सामने रखी।

वहीं, सिल्ला एवं भेलाटीपरी गांवों के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अवरुद्ध सड़क मार्गों को सुचारू करने और प्रभावित परिवारों को प्रतिकर राशि शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सभी फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उत्तरकाशी में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य पखवाड़ा, 208 शिविरों में जांच, दवा वितरण और रक्तदान शिविर

डायबिटीज, कैंसर जांच से लेकर निःशुल्क दवा वितरण और चश्मों तक की होगी व्यवस्था

स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा, जिलाधिकारी ने जनसहभागिता पर दिया जोर

रक्तदान शिविरों में होगा पंजीकरण, वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी विशेष सुविधा

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। प्रदेशभर की तर्ज पर उत्तरकाशी जनपद में भी आगामी 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य पखवाड़ा बृहद स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से लेकर जिला चिकित्सालय स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। वहीं राज्य स्तर पर देहरादून व नैनीताल में मेगा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पखवाड़े के अन्तर्गत प्रदेशभर में 2300 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डायबिटीज, कैंसर सहित अन्य रोगों की जांच, स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क औषधि वितरण और ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 250 से अधिक केंद्रों पर रक्तदान शिविर लगाकर लोगों का पंजीकरण किया जाएगा। खासतौर से 17 सितम्बर को राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में एक साथ विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को प्रचार-प्रसार पर विशेष बल देने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि जनपद में स्वास्थ्य पखवाड़े की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को देखते हुए अन्य विभागों की सहभागिता भी सुनिश्चित की गई है और जनसहभागिता पर भी विशेष जोर दिया गया है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एस. रावत ने जानकारी दी कि जनपद में 17 सितम्बर से 208 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर मेगा स्वास्थ्य कैम्प भी आयोजित होंगे। इन शिविरों में दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने, आवश्यक स्वास्थ्य जांच-परीक्षण, निःशुल्क दवाई वितरण और वरिष्ठ नागरिकों को डॉक्टर की सलाह पर चश्मों का वितरण जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

भूस्खलन से तबाह नैडा-लोहरियाणा ग्रामीणों का जिलाधिकारी को ज्ञापन, प्रभावित परिवारों को राहत व सुरक्षित ठिकाने की मांग

डॉ. स्वराज विद्वान की अगुवाई में सौंपा गया ज्ञापन, जिलाधिकारी ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। हरेती, नैडा एवं पैंथर लोहरियाणा के ग्रामीणों ने शुक्रवार को डॉ. सुश्री स्वराज विद्वान राष्ट्रीय मंत्री भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा एवं प्रभारी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व में जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य से भेंट कर विस्थापन और मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

डॉ. विद्वान ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण कार्य के कारण नैडा क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे कई परिवारों की खेती कट चुकी है और मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत, सुरक्षित आश्रय और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की।

इस अवसर पर डॉ. सुश्री स्वराज विद्वान ने कहा कि नैडा और लोहरियाणा क्षेत्र के ग्रामीण राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण की कीमत अपनी खेती और घरों की तबाही से चुका रहे हैं। लगातार भूस्खलन से खेत कट रहे हैं, मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और लोग असुरक्षित जीवन जीने को मजबूर हैं। प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत, सुरक्षित ठिकाना और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। प्रशासन ने हमारी मांगों को गंभीरता से लिया है और त्वरित निर्देश दिए हैं। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पीड़ित परिवार उपेक्षित न रहे। ग्रामीणों के अधिकार और उनकी सुरक्षा की रक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता है।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर गंभीरता दिखाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार डुंडा को नैडा व लोहरियाणा के प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने और किराये पर रहने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इसी के साथ गेंवला गांव के ऊपर हो रहे भूस्खलन और पानी रिसाव की समस्या पर जिलाधिकारी ने 15 सितम्बर को भूवैज्ञानिकों की टीम को मौके पर भेजने और शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं उपस्थित ग्रामीणों की कई छोटी-छोटी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

इस अवसर पर ग्राम प्रधान हरेती, क्षेत्र पंचायत सदस्य हरेती, पूर्व प्रधान नरेश, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रवि, जिला पंचायत सदस्य भण्डारस्यूं बुद्धि सिंह राणा, जयप्रकाश, ओमप्रकाश, गिरीश रावत, मोहन जोगिला सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी की तत्परता पर संतोष जताया और डॉ. स्वराज विद्वान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व से प्रभावित परिवारों की आवाज़ प्रशासन तक पहुँची और उन्हें शीघ्र राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

एक नजर

बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा : स्कूटी सवार महिला की मौत, पति घायल

पथ प्रवाह, संदीप बर्तवाल। बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ से करीब 12 किलोमीटर पहले गुलाबकोटी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रविग्राम, जोशीमठ निवासी सुधीर बिष्ट अपनी पत्नी ललिता (28) के साथ स्कूटी से जोशीमठ की ओर जा रहे थे। शाम करीब साढ़े पांच बजे गुलाबकोटी में आगे चल रहे एक डंपर को ओवरटेक करने के दौरान स्कूटी सवार ललिता अचानक वाहन की चपेट में आ गई। डंपर महिला को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सीएचसी ज्योतिर्मठ भिजवाया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग व तीर्थयात्री बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए।

पुलिस ने मौके से डंपर चालक गौरव (निवासी पोखरी, चमोली) को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, स्कूटी सवार सुधीर बिष्ट को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है।

आस्था पर भारी पड़ी आपदा

पथ प्रवाह, संवाददाता, सिद्धार्थ त्रिपाठी की रिपोर्ट

पहाड़ों पर हो रही भारी बारिशों के कारण पूरे प्रदेश में जगह जगह आपदाएं आई हुई हैं। जिनके कारण पूरे प्रदेश में तीर्थाटन लगभग बन्द पड़ा है। जिससे प्रदेश में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कमी आई हुई है।

प्रदेश भर में आई इस आपदा के असर से हरिद्वार भी अछूता नहीं है। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है जहां पहले आजकल के दिनों में इन दिनों हरिद्वार में गंगा घाटों और बाजारों में यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ रहती थी वहीं आज कल सब कुछ सुनसान पड़ा है। पहले इन दिनों में हर की पैड़ी और उसके आसपास के घाटों पर लोग की भीड़ सुबह से ही अपने पित्रों के निमित्त पिण्डदान, श्राद्ध, तर्पण के लिए इकट्ठी हो जाती थी। वहीं इस बार सब ये घाट यात्रियों का इंतजार करते दिख रहे है।

हरकी पैड़ी, सुभाष घाट, कुशा घाट, राम घाट सभी खाली नजर आ रहे हैं। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों की माने तो हर बार के औसत में इस बार दस प्रतिशत भी तीर्थ यात्री अभी हरिद्वार नहीं पहुंचा है। सिर्फ नारायणी शिला मन्दिर और उसके आसपास के कुछ घाटों पर कुछ चहल पहल नजर आ रही है। नारायणी शिला मन्दिर, गणेश घाट और अमरापुर घाट,पर कुछ तीर्थ यात्री पिंडदान करते दिखते है। उनमें भी अधिकतर स्थानीय लोग या हरिद्वार के आसपास के क्षेत्रों के लोग ही है। दूर के लोग हरिद्वार आने से बच रहे है।

हरिद्वार के व्यापारी भी इस वजह से काफी चिंतित नजर आ रहे है। व्यापारियों का कहना है कि सामान्य दिनों में इन पंद्रह दिनों में इतना काम हो जाता था जिसमें वह आने वाले अगले महीने में होने वाली भारी मंदी के लिए कुछ व्यवस्था कर के रख सकते थे। परन्तु इस वर्ष तो इतना भी काम नहीं हो रहा है कि दैनिक खर्चे पूरे हो सके ।

आपको बता दे कि श्राद्ध पक्ष के तुरन्त बाद नवरात्र शुरु हो जाते है जिस कारण इन दिनों लोग घर पर रहकर ही पूजा पाठ करना पसंद करते है और उसके बाद दशहरे से दिवाली तक गंगा सफाई के लिए गंगा जी का सालाना क्लोजर हो जाता है और यात्रियों की आवत एकदम से लगभग बन्द हो जाती है। इन्हीं दिनों में सारे बड़े त्योहार पड़ते है जिस कारण श्राद्ध पक्ष पर ही हरिद्वार के लोगों की आजीविका की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हालफिलहाल भी मौसम के हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे है और मौसम विभाग प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रहा है । ऐसे में हरिद्वार के व्यापारियों और पुरोहितों के लिए समस्या बढ़ भी सकती है।

उत्तराखंड क्रांति दल का दिवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़

आज 12 सितंबर 2025 पिथौरागढ़ उत्तराखंड क्रांति दल का वार्षिक अधिवेशन मां कृपा बारात घर में संपन्न हुआ जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेता काशी सिंह एरी सभा के अध्यक्ष चंद्रशेखर कापड़ी की अध्यक्षता में तथा संयोजक चंद्रशेखर पुनेडा के संयोजकतत्व में चुनाव संपन्न हुए जिसमें पर्यवेक्षक माननीय सलीम अहमद तथा प्रभारी निर्मल चौधरी जी थे चुनाव अधिकारी हरि जोशी थे ।

सदन में ध्वनि मत से लगातार नवीं बार चंद्रशेखर पुनेडा को जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया महानगर अध्यक्ष पद पर राम सिंह को निर्विरोध निर्वाचित किया गया जिला उपाध्यक्ष पद पर हीरा बल्लभ भट्ट तथा पुष्कर सिंह चौहान, जिला महामंत्री पद पर मदन पोखरिया जिला कोषाध्यक्ष पद पर प्रेम सिंह बोहरा युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष के पद पर गिरीश चंद्र जोशी को निर्विरोध और अनुसुचित जनजाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कोहली और रा0आ0प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिलीप धामी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया अधिवेशन में जनपद चंपावत की भी अध्यक्ष व महामंत्री का चुनाव वहां से आए कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया जिसमें चुनाव प्रभारी माननीय चंद्रशेखर पुनेडा पर्यवेक्षक माननीय जगत मेहता ,चुनाव प्रभारी प्रहलाद सिंह मेहता उपस्थित थे ।

पिथौरागढ़ पुलिस का मानवीय चेहरा : रास्ता भटके बालक को सकुशल घर पहुंचाया

जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़। 12 सितंबर 2025 - पिथौरागढ़ पुलिस ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए एक भटके हुए बालक को उसके परिवार से मिलाया। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर शाम लगभग 7 बजे वड्डा बाजार क्षेत्र में एक मासूम बालक अकेले और परेशान हालत में घूमता हुआ मिला। चौकी प्रभारी वड्डा, उपनिरीक्षक आशीष रावत व उनकी टीम (कांस्टेबल ललित कांडपाल, कांस्टेबल मनोहर कापड़ी व होमगार्ड मुकेश भट्ट) ने तुरंत बच्चे को अपने संरक्षण में लिया और उससे पूछताछ की। बच्चे ने बताया कि वह ऐचोली का निवासी है और रास्ता भटक गया था। इसके बाद पुलिस टीम ने चौकी प्रभारी ऐचोली उपनिरीक्षक कमलेश जोशी से संपर्क साधकर उसके घर का पता लगाया। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस की इस मानवीय पहल से बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और परिजन भी राहत व कृतज्ञता से

भर उठे। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस टीम की संवेदनशीलता की सराहना की।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के सुशासन के दावे को सच साबित कर रहे हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित

नवीन चौहान, संवाददाता

हरिद्वार में जहां गंगा की धारा आस्था और विश्वास का प्रतीक है, वहीं अब सुशासन की धारा भी बह रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन के दावे को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित अपने काम से सही साबित कर रहे हैं। संवेदनशीलता और सख्ती का अद्भुत संतुलन उनकी पहचान बन चुका है।

पहली कॉल पर मदद, तुरंत कार्रवाई

प्रशासनिक सेवा का असली उद्देश्य जनता तक न्याय और सुविधा पहुंचाना है। मयूर दीक्षित इस उद्देश्य को पूरी गंभीरता से निभाते हैं। किसी भी शिकायतकर्ता या जरूरतमंद की कॉल पर वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और विभागीय टीम को सक्रिय कर समाधान सुनिश्चित करते हैं। यही वजह है कि लोग कहते हैं - ÷डीएम साहब भरोसे का नाम हैं।÷

अतिक्रमण पर सख्त रुख

तीर्थनगरी हरिद्वार में अतिक्रमण लंबे समय से एक चुनौती रहा है। लेकिन मयूर दीक्षित ने इसे हल्के में नहीं लिया। हाल ही में रानीपुर मोड़, रोडवेज बस स्टैंड और तमाम प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों से अवैध कब्जे हटवाकर उन्होंने प्रशासन की सख्त छवि सामने रखी। शहर की सूरत निखरी और जनता ने राहत की सांस ली।

पीड़ितों को न्याय दिलाने में भरोसा

डीएम मयूर दीक्षित की सबसे बड़ी खूबी उनकी संवेदनशीलता है। चाहे भूमि विवाद का मामला हो, मुआवज़े की देरी या किसी विभाग की लापरवाही - वे पीड़ितों की आवाज़ को प्राथमिकता देते हैं। कई मामलों में उनकी सीधी हस्तक्षेप से लोगों को न्याय मिला है।

मुख्यमंत्री की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अग्रणी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकताओं - महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार, बुनियादी ढांचे का विकास - को जनता तक पहुंचाने में जिलाधिकारी दीक्षित अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। वे न केवल बैठकों तक सीमित रहते हैं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से योजनाओं की प्रगति की निगरानी करते हैं।

जनता का बढ़ता भरोसा

गुरुकुल कांगड़ी निवासी राजेंद्र कहते हैं - डीएम साहब का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। वे शिकायत को टालते नहीं, बल्कि तुरंत कार्रवाई करते हैं।

व्यापार मंडल से जुड़े एक पदाधिकारी का कहना है - अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्ती ने बाजारों को राहत दी है।

वहीं छात्रा पायल मेहता का कहना है - महिला सुरक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं पर डीएम साहब की निगरानी से हमें भरोसा मिला है।

समापन: सुशासन का चेहरा

हरिद्वार के लोग आज यह मानने लगे हैं कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित केवल एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि जनता के दुख-सुख में साझेदार हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन का विज़न ज़मीनी हकीकत में बदल रहा है, और इसका सबसे जीवंत उदाहरण हरिद्वार के जिलाधिकारी हैं।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ली समीक्षा बैठक, आपदा प्रभावित किसानों को राहत देने के निर्देश

पथ प्रवाह, संवाददाता

सूबे के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुई क्षति को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने जनपद उत्तरकाशी में सी-ग्रेड के फलों के लिए तीन दिन के भीतर कांटा लगाने के निर्देश दिए। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली में अधिक से अधिक किसानों को एप्पल मिशन के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को जायका

परियोजना पर कार्य तेज करने, नवंबर माह से प्लांटेशन शुरू करने और जायका का कैलेंडर शीघ्र जारी करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने घेरबाड़ के बकाया भुगतान को तत्काल करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सहायक कृषि अधिकारियों के वेतन विसंगतियों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सहायक कृषि अधिकारियों ग्रेड - 3 और ग्रेड - 2 की तैनाती पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की बाध्यता समाप्त करने का प्रस्ताव भेजें। मंत्री ने विभाग में मॉली के रिक्त 400 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया 30 सितम्बर तक पूर्ण करने के भी आदेश दिए। इस अवसर पर सचिव कृषि एसएन पांडेय, कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मोदी जायेंगे मणिपुर, 8500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लंबे समय तक चली जातीय हिंसा से उबर रहे मणिपुर का शनिवार को दौरा करेंगे और राज्य को 8500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद श्री मोदी का राज्य का यह पहला दौरा है। वहां वह 8500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। विपक्ष मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से ही शांति बहाली के लिए प्रधानमंत्री के वहां जाने की मांग करता रहा है। मणिपुर में इसी

वर्ष फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि श्री मोदी शनिवार सुबह पहले मिजोरम जायेंगे जहां से वह साढे बारह बजे मणिपुर पहुंचेंगे और राज्य के समावेशी, सतत और समग्र विकास के प्रति सरकार की वचनबद्धता के अनुरूप चुड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की शहरी सड़कें, जल निकासी और संपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना, 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ , मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट परियोजना और नौ स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं। वह इस अवसर पर वहां मौजूद जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री अपराह्न ढाई बजे राजधानी इंफाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें मंत्रीपुखरी में नागरिक सचिवालय, मंत्रीपुखरी में आईटी एसईजेड भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन, और चार जिलों में महिलाओं के लिए अद्वितीय बाजार, इमा मार्केट शामिल हैं। श्री मोदी इंफाल में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

मोदी की मां के एआई वीडियो पर बिफरी भाजपा

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां को गाली देना का मामला शुक्रवार सुबह बिहार कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया एक्स हैंडल से कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) द्वारा निर्मित वीडियो जारी करने के बाद एक बार फिर से सुलग उठा है। एआई वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां का जानबूझकर और बार-बार अपमान देश और बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। इस वीडियो को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि उनकी (प्रधानमंत्री मोदी) दिवंगत मां के प्रति अनादर कहां है, मुझे एक शब्द, एक इशारा, कहीं भी दिखाइए जहां आप अनादर देखते हैं। कांग्रेस के एआई वीडियो पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेशर्मी पर उतर आयी है। पहले कांग्रेस के मंच से श्री मोदी की मां को गाली दी गयी और अब एआई वीडियो बनाकर उनकी मां का अपमान कर रही है। जिस तरह कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की मां का वीडियो बनाया है, जो अब इस दुनिया में भी नहीं हैं उनके बारे में इस तरह का वीडियो बनाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इससे बाज आए। पूरे देश और बिहार की जनता उस मां के अपमान का बदला जरूर लेगी, जो अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस वीडियो को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर प्रधानमंत्री की मां का अपमान कर रही है। यह अब गांधी की कांग्रेस नहीं रही, यह गालियों की कांग्रेस बन गयी है। वहीं, एक अन्य भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान लगातार कर रही है।

एक नजर

मुनस्यारी के बॉक्सरों का शानदार प्रदर्शन, वृंदावन प्रतियोगिता में कई पदक जीते

जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़। 12 सितंबर 2025 - सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के उभरते हुए बॉक्सरों ने वृंदावन में आयोजित क्षेत्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। 08 से 10 सितंबर तक आयोजित इस टूर्नामेंट में अंडर-14 वर्ग में तरुण बोरा और सागर सिंह ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि विकास जेष्ठा ने रजत पदक हासिल किया। अंडर-17 वर्ग में कृष्णा राणा और सागर कोहली ने रजत पदक जीता। वहीं अंडर-19 वर्ग में अजय वर्मा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी पिथौरागढ़, अनूप बिष्ट ने बताया कि तरुण बोरा, सागर सिंह और अजय वर्मा का चयन अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो गया है। ये तीनों खिलाड़ी 06 से 08 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। सभी खिलाड़ी मुनस्यारी के जोहार खेल मैदान में कोच महिमा विश्वकर्मा से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुनस्यारी के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष कमल पुनेड़ा, सचिव अजय राठौर, कोषाध्यक्ष बहादुर सिंह बोहरा सहित खेल प्रेमियों ने खुशी जताते हुए सभी विजेताओं को बधाई और आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

राजनीतिक दलों की पारदर्शिता विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन के लिए व्यापक नियम बनाने का निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने के साथ ही मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर संबंधित आदेश पारित किया। पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा, ÷हम नोटिस जारी करेंगे लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो सकती है कि हमने राजनीतिक दलों को पक्षकार नहीं बनाया है। वे कहेंगे कि आप (याचिकाकर्ता) उन्हें विनियमित करने के लिए कह रहे हैं और वे यहाँ नहीं हैं। याचिका में दावा किया गया है कि दसवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक स्थिति और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29ए के तहत वैधानिक मान्यता के बावजूद, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज, पारदर्शिता या जवाबदेही को विनियमित करने के लिए कोई व्यापक कानून मौजूद नहीं है। याचिकाकर्ता की यह भी दलील है कि राजनीतिक दल आयकर अधिनियम की धारा 13ए के तहत कर छूट के अलावा दूरदर्शन/आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण समय सहित सरकार की ओर से उपलब्ध कई सुविधाएं लेते हैं, फिर भी वे अनियमित हैं। याचिका में मुख्य रूप से मांग की गयी है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा भारत संघ (सरकार) को पारदर्शिता, आंतरिक दलीय लोकतंत्र और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु व्यापक कानून बनाने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा, भ्रष्टाचार, काले धन के रूपांतरण और राजनीति के अपराधीकरण के साधन के रूप में राजनीतिक दलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

स्वामी/प्रकाशक **वीरेन्द्र सिंह** ने मुद्रक **प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)** से मुद्रित कराकर, **मुख्य कार्यालय: 41, शांतिपुरम, जगजीपुर, कनखल, हरिद्वार पिन–249408 (उत्तराखण्ड)** से प्रकाशित किया। **वीरेन्द्र सिंह** (सम्पादक) 9411111733, **सुरेन्द्र पाल सिंह** (ब्यूरो चीफ, उत्तरकाशी) 7376757899 वेबसाई– www.pathpravah.com